RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 210
दि. 04.05.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पुणे की दर्दनाक वारदात ने झकझोरा देश, सख्त कार्रवाई के साथ न्याय की मांग तेज

महाराष्ट्र के पुणे जिले से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या की इस वारदात ने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि कानून-व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है, ताकि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा सके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।

घटना पुणे जिले की भोर तहसील के एक गांव की है, जहां एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने मासूम को खाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। यह वही भरोसा था, जो बच्चों के सहज स्वभाव का हिस्सा होता है और जिसे अपराधी ने अपनी दरिंदगी के लिए इस्तेमाल किया। आरोप है कि वह बच्ची को एक पशु बाड़े में ले गया, जहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और बाद में पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि मानवता के मूल्यों पर एक गहरा आघात है।

पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उसे 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जा सके। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिससे यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति समाज में खुलेआम कैसे घूम रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छह सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जिसमें दो महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इस टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह हर पहलू की बारीकी से जांच करे—चाहे वह घटनास्थल के साक्ष्य हों, आरोपी की पृष्ठभूमि हो या फिर किसी अन्य संभावित संलिप्तता की जांच। जरूरत पड़ने पर इस टीम का विस्तार भी किया जा सकता है। यह कदम इस बात का संकेत है कि प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस घटना के बाद पूरे इलाके में गहरा आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग को घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। यह गुस्सा केवल एक घटना का नहीं, बल्कि उन तमाम घटनाओं का प्रतिबिंब है, जो समय-समय पर सामने आती हैं और लोगों के भीतर असुरक्षा और आक्रोश को जन्म देती हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इस घटना ने हलचल पैदा कर दी है। कई दलों के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है, हालांकि बच्ची के पिता ने इस कठिन समय में गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कोई उनसे मिलने न आए। यह अपील इस बात को दर्शाती है कि परिवार इस समय केवल न्याय चाहता है, न कि किसी प्रकार की राजनीतिक या सार्वजनिक सहानुभूति।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि सरकार आरोपी को फांसी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इस मामले की सुनवाई 'रिकॉर्ड समय' में पूरी कराई जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री का यह बयान सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी हो।

यह घटना केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज के नैतिक ढांचे पर भी सवाल खड़ा करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसे अपराध क्यों होते हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जागरूकता, सतर्कता और सख्त कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके साथ ही, यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में जांच और न्याय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो। अक्सर देखा गया है कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया पीड़ित परिवार के लिए एक अतिरिक्त मानसिक बोझ बन जाती है। इसलिए 'फास्ट ट्रैक' सुनवाई और सख्त सजा न केवल न्याय दिलाने के लिए, बल्कि समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।

अंततः, पुणे की यह घटना एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि अभी भी समाज में ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो मानवता के हर मानक को तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी उम्मीद जगाती है कि यदि प्रशासन, न्याय व्यवस्था और समाज मिलकर सख्ती और संवेदनशीलता के साथ काम करें, तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

नेपाल में नियुक्तियों पर सर्जिकल स्ट्राइक पारदर्शिता बनाम अस्थिरता की नई बहस

काठमांडू से आई एक अहम प्रशासनिक खबर ने नेपाल की राजनीति और शासन व्यवस्था में हलचल मचा दी है। रामचंद्र पौडेल द्वारा जारी अध्यादेश के बाद नई सरकार ने एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठाते हुए 1,500 से अधिक सरकारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय 26 मार्च से पहले की गई सभी नियुक्तियों पर लागू किया गया है, जिससे अचानक कई महत्वपूर्ण पद खाली हो गए हैं और प्रशासनिक ढांचे पर इसका सीधा असर पड़ने लगा है। इस फैसले के केंद्र में हैं बालेंद्र शाह, जिनके नेतृत्व में बनी सरकार ने सत्ता संभालते ही यह सख्त कदम उठाया है।

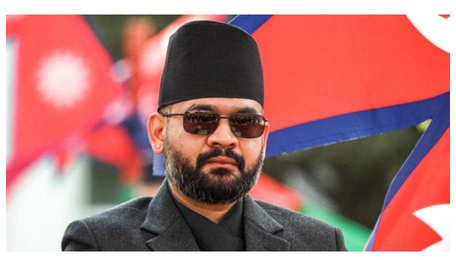

सरकार का तर्क स्पष्ट है कि जिन नियुक्तियों को रद्द किया गया है, वे राजनीतिक प्रभाव के आधार पर की गई थीं और उनमें पारदर्शिता तथा योग्यता की अनदेखी हुई थी। "सार्वजनिक पदधारकों को हटाने के लिए विशेष प्रावधान, 2083" नामक अध्यादेश के तहत कुल 1,594 लोगों को उनके पदों से हटाया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था को शुद्ध किया जा सकेगा और भविष्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और जवाबदेह बनेगी। यह संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ शासन के तौर-तरीकों में भी बदलाव लाया जाएगा।

हालांकि, इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है—क्या यह कदम वास्तव में पारदर्शिता की दिशा में सुधार है, या फिर यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए? विपक्ष और कई विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों को एक झटके में रद्द करना प्रशासनिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। उनका तर्क है कि जिन पदों पर लोग काम कर रहे थे, उनके अचानक हटने से न केवल कार्य प्रभावित होगा, बल्कि संस्थागत निरंतरता भी टूटेगी।

इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव उन प्रमुख संस्थानों पर पड़ सकता है, जो देश की आधारभूत संरचना और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान और नेपाल एयरलाइंस जैसे संस्थानों में कई अहम पद खाली हो गए हैं। इन संस्थानों की कार्यप्रणाली पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, और अब अचानक हुए इस बदलाव से उनके संचालन पर और दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन रिक्त पदों को जल्द नहीं भरा गया, तो सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इन खाली पदों को कैसे और कब भरेगी। फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं आया है। एक और अध्यादेश राष्ट्रपति के विचाराधीन बताया जा रहा है, लेकिन उसमें भी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। यह अनिश्चितता न केवल प्रशासनिक तंत्र में असमंजस पैदा कर रही है, बल्कि आम जनता के बीच भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या यह बदलाव स्थायी सुधार की दिशा में है या केवल एक अस्थायी राजनीतिक कदम।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थागत मजबूती की परीक्षा बन गया है। एक ओर सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे सत्ता के केंद्रीकरण और प्रशासनिक हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि किसी भी सुधारात्मक कदम को लागू करते समय संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी होता है। नेपाल जैसे देश में, जहां राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, ऐसे फैसलों का प्रभाव केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यापक राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। यदि सरकार इस कदम के साथ एक स्पष्ट और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया प्रस्तुत करती है, तो यह सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। लेकिन यदि अनिश्चितता बनी रहती है, तो यह निर्णय सरकार के लिए ही चुनौती बन सकता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि नेपाल में लिया गया यह फैसला एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह प्रशासनिक शुद्धिकरण और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर इससे उत्पन्न अस्थिरता और अनिश्चितता भी कम चिंताजनक नहीं है।

मध्यप्रदेश के विकास की नई रेखा: इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलता आर्थिक नक्शा

मध्यप्रदेश में औद्योगिक और शहरी विकास की दिशा में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने जिस महत्वाकांक्षी इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी है, उसे केवल एक सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास मॉडल को बदलने वाली रणनीतिक योजना के रूप में देखा जा रहा है। 2360 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के प्रथम चरण का भूमि पूजन इंदौर के नैनोद गांव में किया गया, जहां किसानों की भागीदारी ने इस परियोजना को एक सामाजिक सहमति का रूप भी दे दिया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब विकास केवल ऊपर से थोपे जाने वाली प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों, विशेषकर किसानों को सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। कार्यक्रम में किसानों ने न केवल मुख्यमंत्री का स्वागत किया, बल्कि भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति पत्र भी सौंपे, जो इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक समर्थन माना जा रहा है।

सरकार ने इस परियोजना में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए एक नया मॉडल अपनाया है। किसानों को उनकी भूमि के बदले चार गुना मुआवजा देने के साथ-साथ 60 प्रतिशत विकसित भूखंड लौटाने का निर्णय लिया गया है। यह नीति पारंपरिक भूमि अधिग्रहण मॉडल से अलग है, जिसमें अक्सर किसानों को केवल मुआवजा दिया जाता था और वे विकास की प्रक्रिया से बाहर रह जाते थे। अब इस नए मॉडल में किसान सीधे विकास के लाभार्थी बन रहे हैं। इसी वजह से इसे एक "भागीदारी आधारित विकास मॉडल" कहा जा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक किसानों को लगभग 650 करोड़ रुपये मूल्य के प्लॉट वितरित किए जा चुके हैं। इसका सीधा प्रभाव यह पड़ा है कि कई किसान अब केवल कृषि पर निर्भर न रहकर स्थायी आय के नए स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह इकोनॉमिक कॉरिडोर केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक शहरी-औद्योगिक नेटवर्क का हिस्सा है। प्रस्तावित 8-लेन सुपर एक्सप्रेस वे इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर और रतलाम जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ते हुए एक बड़े मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा। यह कॉरिडोर आगे चलकर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से भी जुड़ जाएगा, जिससे अंतरराज्यीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बड़ी मजबूती मिलेगी। इस परियोजना के माध्यम से एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और वेयरहाउसिंग जैसे उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। खासकर युवाओं के लिए यह कॉरिडोर एक नए आर्थिक भविष्य का द्वार खोल सकता है। तकनीकी और भौगोलिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 20.28 किलोमीटर लंबे और 1316 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस कॉरिडोर में 75 मीटर चौड़ी आधुनिक सड़क बनाई जाएगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-47 और 52 को जोड़ते हुए परिवहन व्यवस्था को तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल बनाएगा। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि औद्योगिक माल ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा।

सरकार का दावा है कि यह परियोजना मध्यप्रदेश में संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा देगी। अभी तक विकास मुख्य रूप से कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा है, लेकिन इस कॉरिडोर के जरिए आसपास के छोटे और मध्यम शहर भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार होगा। इस परियोजना को लेकर राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे देश की सर्वश्रेष्ठ विकास योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रीन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इसे विकास और प्रगति का प्रतीक बताया और कहा कि यह परियोजना प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। इस पूरे मॉडल का सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसमें किसानों को केवल जमीन देने वाला नहीं, बल्कि विकास में साझेदार माना गया है। यह दृष्टिकोण भारतीय विकास नीतियों में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। पहले जहां भूमि अधिग्रहण अक्सर विरोध और विवाद का कारण बनता था, वहीं अब सहमति और भागीदारी के आधार पर विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। हालांकि, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होतीं। भूमि उपयोग, पर्यावरणीय संतुलन, विस्थापन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर लगातार निगरानी की आवश्यकता होगी।

एक दिल, कई धड़कनें: अंगदान के फैसले ने लिखी नई जिंदगी की कहानी

नई दिल्ली में एक मार्मिक और प्रेरणादायक घटना ने यह साबित कर दिया कि मानवता का सबसे बड़ा रूप वही है, जब कोई अपने दुख के क्षण में भी दूसरों के जीवन के बारे में सोच सके। एक सेना अधिकारी के परिवार ने अपार दुख के बीच ऐसा साहसिक निर्णय लिया, जिसने न केवल एक 14 वर्षीय बच्चे को नई जिंदगी दी, बल्कि कई अन्य जरूरतमंदों के लिए भी उम्मीद की किरण जगा दी। यह घटना केवल एक चिकित्सकीय सफलता नहीं, बल्कि संवेदनाओं, त्याग और जीवन के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक बन गई है।

हरियाणा के पंचकूला स्थित कमांड अस्पताल में भर्ती 41 वर्षीय महिला को ब्रेन हेमरेज के बाद डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अंततः 2 मई को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। यह वह क्षण था, जब किसी भी परिवार के लिए सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग अपने दुख में डूब जाते हैं, लेकिन इस परिवार ने एक अलग रास्ता चुना। महिला के पति और उनकी बेटियों ने अंगदान का निर्णय लेकर यह साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धांजलि वही है, जो किसी और की जिंदगी को बचा सके।

इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ एक 14 वर्षीय बच्चे को मिला, जो पिछले एक वर्ष से हार्ट फेल्योर से जूझ रहा था। उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों के अनुसार, हार्ट ट्रांसप्लांट ही उसकी जान बचाने का एकमात्र विकल्प था। जब महिला का हृदय उपलब्ध हुआ, तो तुरंत उसे नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती बच्चे के लिए निर्धारित किया गया। यह एक ऐसा क्षण था, जहां समय के हर सेकंड की कीमत थी।

दिल को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए चिकित्सा और प्रशासनिक तंत्र ने अभूतपूर्व समन्वय दिखाया। जैसे ही हृदय प्रत्यारोपण के लिए तैयार हुआ, मेडिकल टीम तुरंत चंडीगढ़ पहुंची। वहां से दिल को लाने के लिए विशेष चार्टर्ड विमान का उपयोग किया गया, ताकि दूरी कम समय में तय की जा सके। दिल्ली पहुंचने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया, जिसके माध्यम से महज 20 मिनट में दिल को अस्पताल तक पहुंचाया गया। इस दौरान सड़कों को पूरी तरह खाली कराया गया, ताकि किसी भी प्रकार की देरी न हो। यह पूरा अभियान एक सटीक और सुव्यवस्थित प्रयास का उदाहरण था, जिसमें हर इकाई ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाया।

जब दिल अस्पताल पहुंचा, तो डॉक्टरों की टीम पहले से ही तैयार थी। सर्जरी तुरंत शुरू की गई और कई घंटों के प्रयास के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चे को आईसीयू में रखा गया, जहां वह डॉक्टरों की निगरानी में है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। यह खबर न केवल उसके परिवार के लिए राहत लेकर आई, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी, जो अंगदान के महत्व को समझते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि बच्चे का नाम पहले से ही राष्ट्रीय अंग एवं टिशु ट्रांसप्लांट संगठन में पंजीकृत था। यही कारण था कि जैसे ही उपयुक्त अंग उपलब्ध हुआ, उसे प्राथमिकता के आधार पर यह जीवनदायी अवसर मिल सका। यह व्यवस्था दर्शाती है कि यदि सही प्रणाली और पारदर्शिता के साथ अंगदान प्रक्रिया को संचालित किया जाए, तो अनेक जिंदगियों को बचाया जा सकता है।

अंगदान को लेकर समाज में अभी भी कई तरह की भ्रांतियां और हिचकिचाहट मौजूद हैं। लोग अक्सर भावनात्मक कारणों या जानकारी के अभाव में इस निर्णय से पीछे हट जाते हैं। लेकिन यह घटना यह स्पष्ट संदेश देती है कि अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवता का सर्वोच्च कार्य है। एक व्यक्ति के अंग कई लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं—किसी को दिल, किसी को किडनी, किसी को आंखें—और इस तरह एक जीवन कई जीवनों में बदल सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस पूरे अभियान में डॉक्टरों, नर्सों, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। यदि इनमें से किसी भी स्तर पर थोड़ी भी लापरवाही होती, तो परिणाम अलग हो सकता था। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसने यह साबित किया कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और समर्पण पूर्ण हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है।

इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि जीवन कितना अनमोल है और उसे बचाने के लिए हमें किस हद तक प्रयास करने चाहिए। सेना अधिकारी के परिवार का यह निर्णय न केवल एक बच्चे के जीवन में नई रोशनी लेकर आया, बल्कि समाज को भी एक गहरा संदेश दे गया कि कठिन से कठिन समय में भी यदि हम दूसरों के बारे में सोचें, तो दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है।

अंततः, यह कहानी केवल एक सफल हार्ट ट्रांसप्लांट की नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय भावना की कहानी है, जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि दूसरों को जीने का अवसर देना भी है। अंगदान के इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि एक दिल रुकने के बाद भी कई दिलों को धड़कने की वजह दे सकता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।

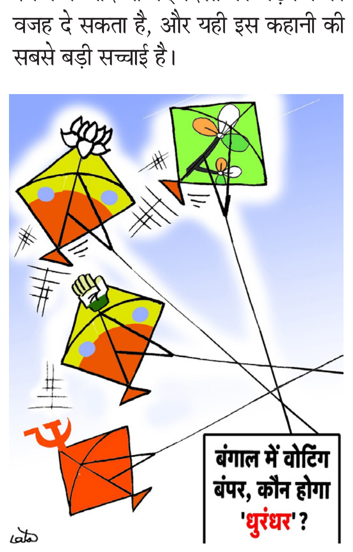

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

आजीविका का संकट बढ़ाएगी बढ़ती गर्मी

एक हालिया आकलन के अनुसार दुनिया के सौ सबसे गर्म शहरों में से 98 भारत में हैं। भीषण गर्मी अपने साथ तमाम मुश्किलें लाती हैं। ये मुश्किलें उस तबके के लिए और विकराल बन जाती हैं, जिन्हें आजीविका के लिए खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि उनके समक्ष आजीविका का संकट पैदा होता है, क्योंकि उनके लिए किए जाने वाले उपाय पर्याप्त नहीं होते। इससे न केवल श्रमिकों, बल्कि देश की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई शोध भी इसी ओर संकेत करते हैं। इस समस्या का समाधान तलाशने की दिशा में इनके निष्कर्षों पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें पहला पैमाना शारीरिक पहलुओं से जुड़ा है। श्री रामचंद्र संस्थान की विद्या वेणुगोपाल, पीके लता और रेखा षणमुगम का 2026 से संबंधित एक अध्ययन 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ है। इसमें तमिलनाडु के 11 जिलों के उन 1,560 श्रमिकों की गतिविधियों पर दो वर्ष तक नजर रखी गई, जिन्हें कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता था। अध्ययन में सामने आया कि गर्मियों के दौरान औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस था, जो 27.5 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम बर्दाश्त योग्य सीमा से भी ऊपर था। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तापमान की इस सीमा से ऊपर निरंतर भारी काम करना असुरक्षित माना जाता है। पर्यवेक्षण समीक्षा के अधीन 88 प्रतिशत श्रमिकों को इस उच्च तापीय परिस्थितियों में काम करना पड़ा। इनमें से 61 प्रतिशत की उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गई। भीषण गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की उत्पादकता में गिरावट की आशंका भी डेढ़ गुना अधिक थी। इनमें 15 प्रतिशत कर्मियों के समक्ष रोजगार छिनने का संकट भी मंडराया, जबकि सर्दियों में उनका प्रतिशत 9.3 ही रहा। दूसरा पहलू वृहद आर्थिक स्तर से जुड़ा है। जर्नल आफ पालिटिकल इकोनमी में सोमनाथन और उनकी टीम का 'उत्पादकता और श्रम आपूर्ति पर तापमान के प्रभाव' शीर्षक से एक शोध प्रकाशित हुआ था। इसमें सूरत के बुनकरों, एनसीआर और हैदराबाद की गारमेंट-सिलाई लाइनों और भिलाई मिल में स्टील शिफ्टों की परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया। इसका निष्कर्ष यह था कि तापमान में प्रति डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर वार्षिक फैक्ट्री उत्पादन में लगभग दो प्रतिशत की गिरावट आई।

हालांकि यह डाटा 2012 तक का ही है, पर इसके निष्कर्षों का निहितार्थ यह है कि गर्मियों का असर पूंजी या कच्चे माल से अधिक श्रम उत्पादकता पर कहीं गहरा पड़ता है। स्पष्ट है कामकाजी स्थल के भीतर एयर कंडीशनर उत्पादकता में गिरावट को तो थाम सकता है, पर उपस्थिति को नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि एसी वाले कार्यस्थल से निकलकर श्रमिकों को आम तौर पर उन्हीं आवासों में जाना पड़ता है, जहां ऐसी सुविधा नहीं होती और पारा अमूमन 45 डिग्री को पार कर जाता है। गर्मी का तीसरा पहलू मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है। इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू में 2024 और 2025 के दौरान सामने आया कि दीमापुर में रेहड़ी लगाने वाली 60 प्रतिशत महिलाओं की सब्जियां गर्मियों में एक ही दिन में खराब हो जाती थीं, जबकि सामान्य दिनों में वे दो-तीन चलती थीं। दिल्ली में 11 से 19 जून, 2024 की हीटवेव में 192 बेघर लोगों की मौत हो गई थी। द लैंसेट काउंटडाउन आन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत ने 2024 में भीषण गर्मी के चलते 247 अरब कामकाजी घंटों का नुकसान झेला, जो 1990 के दशक के औसत की तुलना में 124 प्रतिशत अधिक रहा।

कृषि क्षेत्र को इसका दो तिहाई और कंस्ट्रक्शन उद्योग को 20 प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भीषण गर्मियों के चलते 2030 तक उत्पादकता पर होने वाला आघात आठ करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर होगा। इसकी सर्वाधिक तपिश कृषि और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों को झेलनी पड़ेगी। भारत के लिए यह और हानिकारक है, क्योंकि कामकाजी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में है, जहां सीधे गर्मी के संपर्क में ही काम करना पड़ता है। भारत में श्रमबल का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है और दस प्रतिशत से कम घरों में ही एसी की सुविधा उपलब्ध है। बढ़ती गर्मियों के चलते रोजगार पर संकट की समस्या का समग्रता में समाधान आवश्यक हो गया है। हमारे यहां कई स्थानों पर दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक काम पर पूरी तरह विराम लगाने का प्रविधान है, जिसे बदला जाना चाहिए। इसके बजाय ऐसी व्यवस्था तय की जाए, जिससे कार्यस्थल पर परिस्थितियों के अनुरूप काम को रोका या आरंभ किया जा सके। मौसमी परिस्थितियों के अनुरूप ही काम का पालियों के समय निर्धारण की लचीली व्यवस्था अस्तित्व में आए। सिंगापुर और यूएई में इसी प्रकार का तंत्र प्रभावी है।

शांति स्थापना में मीडिया की आध्यात्मिक दृष्टि मददगार

> वर्तमान अशांत वैश्विक दौर में ब्रह्माकुमारी मिशन आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से शांति स्थापना के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इस मिशन के साथ-साथ मीडिया भी यदि शांति के लिए हो रहे प्रयासों में अपना भरसक योगदान करने लगे तो इस दिशा में विश्व जनमत और मजबूत हो सकता है।

ओम् शांति। वैसे तो 'ओम' रूपी इस अपार शांति सागर में मेरे विचार गागर में एक बूंद की माफिक होंगे। फिर भी वैश्विक शांति के लिए मीडिया की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर अपने अनुभव, अपने विचार और सुझाव रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिये, 'नीड ऑफ ग्लोबल पीस, रोल ऑफ मीडिया' के विषय पर चर्चा की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं :-

कलम उठे तो अमन की कहानी लिखी जाये, हर एक खबर में इंसानियत दिखी जाये।

मीडिया अगर ठान ले दिलों को जोड़ना, तो धरती पर जन्नत की निशानी लिखी जाये।

निस्संदेह, विश्व आज सर्वाधिक अशांत दौर से गुज़र रहा है। चारों तरफ भय और असुरक्षा का माहौल है। व्यक्ति, राष्ट्र से लेकर विश्व स्तर तक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना काल से लेकर, यूक्रेन युद्ध और आजकल अमेरिका-इस्राइल और ईरान द्वंद्व तक के संघर्ष ने दुनिया के अरबों लोगों के जीवन को अशांत बनाकर रख दिया है। हाल के दशकों में वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद दुनिया को एक वैश्विक गांव बनाने का जो सपना देखा गया था वह ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में 'नीड ऑफ ग्लोबल पीस एंड रोल ऑफ मीडिया' विषय आज निश्चित रूप से समय की मांग है।

आज जहां संयुक्त परिवार बिखर कर 'एकल' में सिमटने लगे हैं, दाम्पत्य जीवन में टूटन बढ़ रही है। भागदौड़भरी जिंदगी जी रही युवा पीढ़ी में सहनशीलता, धैर्य का क्षरण हो रहा है। परिवार से लेकर समाज तक और समाज से लेकर देश-विदेश तक मानव मनोविकारों का संत्रास हमारे भाईचारे को, विश्व बंधुत्व के हमारे सपनों को चकनाचूर कर रहा है। सोचा तो यह था कि तकनीकी उन्नति समाज को और देशों को जोड़ने का काम करेगी, लेकिन उलटे दुनिया संघर्षों में उलझी दिखायी पड़ रही है। पूरी दुनिया में युद्ध, मृत्यु, तबाही, विस्थापन और मानवीय विपदाओं का अंतहीन सिलसिला चल निकला है। निस्संदेह ब्रह्माकुमारी मिशन विपदाओं के इस सिलसिले को थामने में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से अथक प्रयास कर रहा है। इस मिशन

के साथ-साथ मीडिया भी शांति के लिए हो रहे प्रयासों में अपना भरसक योगदान करने लगे, अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लग जाये तो इस दिशा में विश्व जनमत और मजबूत हो सकता है। पत्रकार युद्ध का सच बताने के साथ-साथ अगर बुद्ध के सच को भी उजागर करें तो यह समूची मानवता के लिये एक कल्याणकारी ऋषिकर्म होगा। संयोग से आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसके लिए आप सबको बधाई!

इस मंच से उल्लेख जरूरी है कि जिस नारी के महत्व, जिस नारी की शक्ति को आज विश्वभर में पहचान मिलने लगी है। जिस नारी का वंदन करते हुए हमारी देश-प्रदेश की सरकारें 33 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रयास और प्रचार कर रही हैं, उस नारी की शक्ति को, उसके महत्व को ब्रह्माकुमारी मिशन के संस्थापक ब्रह्मतुल्य प्रजापिता ने कई दशक पूर्व आंक लिया था। आपकी इस संस्था में 35 या पचास नहीं, बल्कि शत-प्रतिशत आरक्षण नारी शक्ति के लिये कब का हो चुका। आपके प्रणेता जी ने भारतीय संस्कृति के संदेश : 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' को पहले ही आत्मसात् कर लिया।

शांतिप्रिय बंधुओ, बहनो और भाइयो, इस मंच से मुझे यह बताते हुए भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि 'द ट्रिब्यून ट्रस्ट पब्लिकेशन' की हमारी संस्था में भी उच्च पदों पर नारी शक्ति का वर्चस्व है। द ट्रिब्यून की प्रधान संपादक, पंजाबी ट्रिब्यून की संपादक, दैनिक ट्रिब्यून की समाचार संपादक, चंडीगढ़, शिमला और दिल्ली ब्यूरो की प्रमुख के अलावा मानव संसाधन (एचआर) विभाग की प्रमुख भी बहन ही हैं। ट्रिब्यून संस्थान और ब्रह्माकुमारी विवि के मिशन में कई समानताएं भी हैं। ट्रिब्यून की स्थापना करीब 145 साल पहले तत्कालीन अविभाजित भारत के लाहौर में हुई थी और ब्रह्माकुमारी संस्था की स्थापना करीब सौ साल पहले कराची में हुई थी। ट्रिब्यून संस्थान वर्ष 1881 से स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण, सामाजिक सद्भाव और शांति फैलाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

तो चलिये विश्व शांति और इसमें मीडिया की भूमिका विषय पर फिर लौटते हैं। परिवारों से लेकर समाज तक और समाज से लेकर विश्व तक को शांति की माला में पिरोने के लिये निश्चय ही मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है, विश्व शांति के लिये जनमत तैयार कर सकता है और इस तरह जागरूक हुआ जनमत दुनिया के नीति-नियंताओं से यह सवाल कर सकता है कि आखिर शांति के लिये बनाये गये संगठन अपना फर्ज अदा क्यों नहीं कर पा रहे। कौन सी शक्तियां हैं, जो इन संस्थानों को पंगु बना रही हैं। दुनिया के मठाधीशों से पूछा जाना चाहिये कि वैश्विक भाईचारा और विश्व शांति के उद्देश्य से बनाये गये संगठनों, मसलन- संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, जी-ट्वेंटी, जी-सेवन, ब्रिक्स और क्वाड के होते हुए अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियां, इस्राइल और आतंकी शक्तियां मानवता को रौंदने पर क्यों तुली हैं?

अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय मीडिया के मेरे साथियों, उठाओ अपना गांडीव रूपी कलम का अस्त्र, दागो। अरे विश्व शांति के मसीहा का ढोंग रचने वाले महाशक्तिमानो, आप किस हैसियत से नोबेल शांति पुरस्कार पाने की जुगतें भिड़ा रहे हैं। मीडिया के शक्तिमानो जतला दो उन्हें कि कभी न कभी शांति का उजाला उनके झूठ के अंधकार को अवश्य निगल जायेगा। ऐसे हथियार विक्रेताओं को एक शायर की यह आवाज सुना दो :-

'तिरे चराग़ अलग हों मिरे चराग़ अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता।'

मीडिया के मेरे दोस्तो, यह सच्चाई हमें माननी पड़ेगी कि सूचना की गति भले तेज हुई है, मगर संवेदना की गहराई कम हो रही है। मानवता के कल्याण के लिये हमें भी ब्रह्माकुमारी मिशनरियों की भांति शांति दूत की भूमिका निभानी होगी। मीडिया समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शक भी है। मीडिया की ताकत पर किसी शायर ने ठीक ही कहा है :-

लफ्जों से ही बनते हैं रिश्तों के कारवां, मीडिया चाहे तो जोड़ दे जहां।

इसलिए आज पीत पत्रकारिता की नहीं, बल्कि पीस पत्रकारिता की जरूरत है। युद्ध की तस्वीरें जरूरी हैं, मगर शांति-वार्ता की मेज की तस्वीरें उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। महात्मा गांधी, बुद्ध, दादी प्रकाशमणि जी जैसे शांति दूतों के संदेश भी मीडिया की सुर्खियां बनें। याद रखिये, सरहदें नहीं रोक सकतीं संवेदनाओं का सैलाब। देश, धर्म, जाति चाहे अलग-अलग हों, दर्द सबका एक सा है। आंसू सबके एक से हैं। खून सबका एक सा है।

ब्रह्माकुमारी दीदी अक्सर कहती हैं, 'विचारों' से संसार बनता है। मीडिया विचारों का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि मीडिया ठान ले तो चौबीस घंटे में पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। ब्रह्माकुमारी मिशन हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। वैश्विक शांति के लिये मीडिया को संक्षेप में ये चार सूत्र देते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। एक- संवाद को संघर्ष पर प्राथमिकता दें। दो- संवेदनशील मुद्दों को संतुलित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें। तीन- सकारात्मक न्यूज़ स्टोरीज को प्रमुखता दें और अंत में चार- आध्यात्मिक मूल्यों करुणा, सहिष्णुता और मानवता को मंच प्रदान करें। ओम शांति।

प्रेरणा

लोक की पुनर्प्रतिष्ठा बनाम सभ्यता का वर्चस्व

भारतीय बौद्धिक परंपरा में 'लोक' और 'सभ्यता' के बीच संबंध हमेशा से जटिल, बहुस्तरीय और कभी-कभी टकरावपूर्ण रहा है। इसी जटिलता को केंद्र में रखते हुए विनोद शाही की नव-प्रकाशित कृति नव लोक-संस्कृति विमर्श एक महत्वपूर्ण और गंभीर हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है। यह पुस्तक केवल सांस्कृतिक विमर्श नहीं, बल्कि उस गहरे द्वंद्व की पड़ताल है जिसमें एक ओर प्रभुत्वशाली सभ्यता है और दूसरी ओर जीवंत, बहती हुई, निरंतर बदलती लोक-संस्कृति। शाही इस द्वंद्व को किसी सतही बहस की तरह नहीं, बल्कि गहरे वैचारिक और ऐतिहासिक संदर्भों में समझने का प्रयास करते हैं।

विनोद शाही की विशेषता यह है कि वे भारतीय चिंतन की जड़ों में उतरते हुए पश्चिमी विचार परंपराओं के साथ संवाद स्थापित करते हैं। इस कारण उनके विचारों में एक व्यापकता और संतुलन दिखाई देता है। वे न तो लोक का अंध-गौरव करते हैं और न ही सभ्यता के विकास को पूरी तरह खारिज करते हैं, बल्कि दोनों के बीच के संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं। यही वजह है कि यह पुस्तक केवल साहित्यिक या सांस्कृतिक पाठ नहीं, बल्कि एक वैचारिक दस्तावेज बन जाती है, जो पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करती है।

पुस्तक की शुरुआत में ही शाही एक मूलभूत प्रश्न उठाते हैं—क्या 'लोक' को सभ्यता के ढांचे में ढाले बिना समझा जा सकता है? उनका तर्क है कि इतिहास में 'लोक' को पहले सभ्य बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, और फिर उसे संस्कृति के रूप में संरक्षित कर लिया गया। इस प्रक्रिया में 'लोक' का जो स्वाभाविक, जीवंत और गतिशील स्वरूप था, वह कहीं न कहीं स्थिर और सीमित कर दिया गया। इस तरह 'लोक' एक जीवित अनुभव से अधिक एक संग्रहालय की वस्तु बनकर रह गया। यहां से शाही उस वर्चस्ववादी संस्कृति की आलोचना करते हैं, जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए लोक को हाशिये पर धकेल देती है। यह वर्चस्व केवल सत्ता के स्तर पर नहीं, बल्कि ज्ञान, भाषा और सौंदर्यबोध के स्तर पर भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए, लोकगीत, लोकनृत्य और लोककला को अक्सर 'परंपरा' के नाम पर संरक्षित तो किया जाता है, लेकिन उन्हें आधुनिक जीवन के केंद्र में स्थान नहीं दिया जाता। वे उत्सवों और आयोजनों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि उनका वास्तविक जीवन-संबंध धीरे-धीरे कमजोर होता जाता है।

शाही इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि लोक-संस्कृति को समझने के लिए उसकी जैव-सामाजिक पुनर्व्याख्या आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि लोक को केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की एक समग्र प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। लोक केवल गीत, नृत्य या कथा नहीं है, बल्कि वह जीवन जीने का तरीका, सामाजिक संबंधों का ढांचा और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध का एक विशिष्ट रूप है। इस दृष्टि से लोक-संस्कृति को समझना एक गहरे मानवीय और सामाजिक अध्ययन की मांग करता है।

पुस्तक के बारह अध्याय इस विमर्श को अलग-अलग आयामों में विस्तार देते हैं। 'लोक और संस्कृति' के संबंध पर चर्चा करते हुए शाही यह स्पष्ट करते हैं कि संस्कृति का प्रभुत्वशाली स्वरूप अक्सर लोक को अपने भीतर समाहित कर लेता है, लेकिन इस समावेशन में उसकी मौलिकता खो जाती है। 'लोक और प्रति-लोक' के संदर्भ में वे उस प्रतिरोध की बात करते हैं, जो लोक के भीतर ही मौजूद रहता है और समय-समय पर प्रभुत्व के खिलाफ उभरता है।

'लोक और साहित्य' के अध्याय में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या साहित्य वास्तव में लोक का प्रतिनिधित्व करता है, या वह भी किसी विशेष वर्ग के दृष्टिकोण से लोक को देखता है। शाही का मानना है कि साहित्य में लोक की उपस्थिति अक्सर प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक नहीं। इसी तरह 'लोक और नाट्य' में वे बताते हैं कि किस तरह लोकनाट्य की परंपराएं आधुनिक रंगमंच के विकास के साथ हाशिये पर चली गईं, जबकि उनमें जीवन की गहरी संवेदनाएं और सामाजिक यथार्थ मौजूद था।

हाशिये के समाजों के सौंदर्यशास्त्र पर चर्चा करते हुए शाही यह स्पष्ट करते हैं कि सुंदरता और कला के मानदंड भी सत्ता द्वारा निर्धारित होते हैं। जो लोक-संस्कृति इन मानदंडों में फिट नहीं बैठती, उसे 'असभ्य' या 'कमतर' मान लिया जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता के लिए भी हानिकारक है।

'लोक और भाषा' के संदर्भ में वे इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि लोकभाषाएं किस तरह धीरे-धीरे हाशिये पर जा रही हैं, और उनकी जगह एक मानकीकृत, औपचारिक भाषा ले रही है। इससे न केवल भाषाई विविधता कम होती है, बल्कि लोक के अनुभवों की अभिव्यक्ति भी सीमित हो जाती है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने और समझने का तरीका भी होती है। इसलिए लोकभाषाओं का क्षरण एक गंभीर सांस्कृतिक संकट है।

'लोक, राजनीति और मिथक' के अध्याय में शाही यह दिखाते हैं कि किस तरह लोकमिथकों का राजनीतिक उपयोग किया जाता है। सत्ता अपने हितों के अनुसार मिथकों की व्याख्या करती है और उन्हें जनमानस पर प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल करती है। इस प्रक्रिया में मिथकों का मूल अर्थ बदल जाता है और वे एक उपकरण बनकर रह जाते हैं।

पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल समस्या की पहचान नहीं करती, बल्कि पाठकों को एक वैकल्पिक दृष्टि भी प्रदान करती है। शाही यह संकेत देते हैं कि लोक-संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। हमें लोक को केवल अतीत की धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखना होगा।

आज के वैश्वीकरण और बाजारवाद के दौर में यह विमर्श और भी प्रासंगिक हो जाता है। बाजार लोक-संस्कृति को एक 'उत्पाद' के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इससे लोक की मौलिकता और उसकी सामाजिक भूमिका कमजोर होती है। ऐसे में शाही की यह पुस्तक हमें चेतावनी देती है कि यदि हमने समय रहते इस प्रवृत्ति को नहीं समझा, तो हमारी सांस्कृतिक विविधता केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह जाएगी।

वैश्विक संकट बना अमेरिका-ईरान का टकराव

होर्मुज समुद्री मार्ग पर ईरान के आधिपत्य जमाने की कोशिश और इसके जवाब में अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते पूरे विश्व में ऊर्जा का न केवल संकट बरकरार है, बल्कि वह गहराता भी जा रहा है। जहां अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों को नहीं निकलने दे रहा है, वहीं ईरान होर्मुज से तेल और गैस लेकर आ रहे जहाजों को रास्ता नहीं दे रहा है। एक तरह से दोनों देश अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। यह तब है, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम भी कायम है।

फिलहाल इस युद्धविराम से दुनिया को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट यथावत है और होर्मुज पहले की तरह बाधित है। ट्रंप ने युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के बाद जब ईरान पर परमाणु मसले पर जल्द समझौते के लिए दबाव डालना शुरू किया तो प्रांरभ में तो वह इस दबाव का प्रतिकार करते दिखा, लेकिन अपने बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी से वह अब कुछ बेचैन दिख रहा है। इसका कारण यह है कि वह जिस तेल का उत्पादन कर रहा है, उसका निर्यात नहीं कर पा रहा है और उसके पास अब और अधिक तेल के भंडारण की क्षमता नहीं बची। ऐसे में उसे अपने तेल कुओं को बंद करना पड़ सकता है। इसके नतीजे में उन्हें स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। शायद इसी कारण ईरान ने पाकिस्तान के जरिये अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन वह ट्रंप को रास नहीं आया। देखना है कि इसके बाद ईरान क्या करता है और ट्रंप क्या करते हैं?

यदि ईरान परमाणु मसले पर समझौते से इन्कार करता रहता है तो ट्रंप उसे नए सिरे से निशाना बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट को लेकर वे अपने घर में ही आलोचना से घिर गए हैं। उनके रक्षा मंत्री विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों को यह बता पाने में नाकाम हैं कि ईरान के खिलाफ चले 40 दिन के युद्ध में अमेरिका को क्या हासिल हुआ? अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता विफल होने और दूसरे दौर की वार्ता कराने में पाकिस्तान के नाकाम हो जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकट सुलझाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, लेकिन इससे भी बात बनती नहीं दिखी। इस बातचीत में रूस ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर बात तभी आगे बढ़ सकेगी, जब ईरान सहमत होगा।

आज यक्ष प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम कायम रहेगा या नहीं, बल्कि यह है कि होर्मुज समुद्री मार्ग खुलेगा या नहीं? यदि यह समुद्री मार्ग नहीं खुलता तो तेल और गैस के दाम नीचे आने वाले नहीं और यदि वे इसी तरह बढ़ते रहे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। कई देशों में तो तेल और गैस के दाम बढ़ भी गए हैं। इसका प्रतिकूल असर उद्योग-धंधों के साथ रोजगार पर भी पड़ रहा है। अभी तक भारत को केवल एलपीजी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस किल्लत के बीच कमर्शियल सिलिंडरों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पिछले कुछ समय से कारखानों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कमी भी देखी जा रही है और उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कहीं-कहीं श्रमिकों के काम के घंटों और दिनों में भी कटौती होने लगी है। एक समस्या यह भी है कि निर्यातक अपना सामान खाड़ी के देश नहीं भेज पा रहे हैं। इसी तरह खाड़ी देशों से तेल और गैस के अलावा अन्य उत्पाद भी नहीं आ पा रहे हैं। इसका भी असर उद्योगों पर पड़ रहा है।

जहां तेल के दाम 125 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गए हैं, वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को लांघ गया है। यह भारत के लिए दोहरा संकट है, क्योंकि इससे आयात बिल बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों और रुपये में गिरावट से महंगाई बढ़ने का खतरा है। अब तो इसकी भी आशंका है कि तेल कंपनियों को अपना घाटा कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो महंगाई का तेजी से बढ़ना तय है। महंगाई बढ़ने से आम आदमी के समक्ष संकट तो बढ़ेगा ही, सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सरकार कुछ भी दावा करे, उसके लिए बहुत दिनों तक पेट्रोल और डीजल के मूल्य स्थिर रखना कठिन होगा। यह ध्यान रहे कि कच्चे तेल के बढ़े दामों के बोझ से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार पहले ही अपने टैक्स राजस्व में कटौती कर चुकी है। इसके तहत पिछले माह पेट्रोल और डीजल, दोनों पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई थी, लेकिन आगे उसके लिए ऐसा करना कठिन होगा। सरकार ने अभी तक भले ही पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे हों, लेकिन उसे कमर्शियल सिलिंडर के दाम बढ़ाने के साथ विदेशी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम बढ़ाने पड़े हैं। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा मंहगी हुई। गत दिवस फिर से एटीएफ के मूल्य बढ़ाए गए। इससे अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा और महंगी होना तय है। कुछ एयरलाइंस की घरेलू यात्रा भी महंगी हो गई है। स्पष्ट है इसका असर आम लोगों के साथ आर्थिकी पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल गैस की ही किल्लत देखने को मिल रही है। चूंकि उर्वरक उत्पादन में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, इसलिए उसके भी दाम बढ़ने और उसकी आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। तारकोल भी पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक उप-उत्पाद है और देश में उसकी भी कमी देखी जा रही है।

यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी रहती है और होर्मुज समुद्री मार्ग नहीं खुलता तो पश्चिम एशिया का संकट पूरी दुनिया के लिए कहीं बड़े संकट में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए केवल अमेरिका और इजरायल ही नहीं, बल्कि ईरान भी दोषी होगा, क्योंकि अब वह भी हठधर्मिता दिखा रहा है। जहां अमेरिका चाह रहा है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को स्थगित करे, वहीं पहले इसी मसले पर अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात कर रहे ईरानी नेता अब यह कह रहे हैं कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि ईरान का यह रुख न तो अमेरिका को स्वीकार होगा, न इजरायल को और न ही खाड़ी देशों को।

अभियान

नरसिंह प्रकट कथा: धर्म, भक्ति और न्याय का शाश्वत संतुलन

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह दृढ़ विश्वास रहा है कि जब-जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचकर धर्म को चुनौती देता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। यही दिव्य सिद्धांत भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रकट होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली नरसिंह जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और भक्ति की उस विराट गाथा का स्मरण है, जो युगों-युगों तक मानवता को दिशा देती रहेगी।

सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था आकार ले रही थी, तब ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार के रूप में अवतार लिया। ये सनकादि मुनि ज्ञान, वैराग्य और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार ये मुनि भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे, लेकिन द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। यह घटना देखने में साधारण लग सकती है, परंतु इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है—जब अहंकार ज्ञान के मार्ग में बाधा बनता है, तब परिणामस्वरूप पतन अवश्य होता है। क्रोधित होकर सनकादि मुनियों ने जय-विजय को राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया।

इस शाप के फलस्वरूप जय और विजय ने सतयुग में दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के अहंकार में पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर समस्त सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया, तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर उसका वध किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने संकल्प लिया कि वह स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि कोई भी उसे पराजित न कर सके।

हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त किया, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसे यह वरदान मिला कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी, न रात में; न धरती पर, न आकाश में; न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से; न किसी मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा और न ही देवताओं द्वारा। यह वरदान उसे अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उसके भीतर अहंकार को भी जन्म देता है। यही अहंकार धीरे-धीरे उसे अत्याचारी बना देता है। उसने न केवल पृथ्वी पर, बल्कि स्वर्ग तक पर अधिकार कर लिया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया।

इस पूरे परिदृश्य में एक अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है—जहां एक ओर पिता अत्याचार और अहंकार का प्रतीक है, वहीं उसका पुत्र प्रह्लाद भक्ति, विनम्रता और सत्य का प्रतीक बनकर उभरता है। प्रह्लाद बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर क्षण, हर परिस्थिति में केवल भगवान का ही स्मरण करते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ, तो उसने क्रूरता का सहारा लिया।

प्रह्लाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए गए—उन्हें विष दिया गया, आग में बैठाया गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई—लेकिन हर बार वे ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बच निकले। यह केवल एक चमत्कारी कथा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि जब किसी के हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, तो वह किसी भी विपत्ति से ऊपर उठ जाता है। प्रह्लाद की अडिग आस्था यह सिद्ध करती है कि भक्ति केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जो जीवन की हर चुनौती को पार कर सकती है।

अंततः वह निर्णायक क्षण आया, जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रह्लाद से पूछा कि उसका भगवान कहां है। प्रह्लाद ने शांत भाव से उत्तर दिया कि भगवान सर्वत्र हैं, यहां तक कि इस खंभे में भी। यह उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया, और उसी क्षण उस खंभे से एक अद्भुत और भयावह रूप प्रकट हुआ—नरसिंह। यह रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था, जो किसी भी श्रेणी में पूरी तरह नहीं आता था।

नरसिंह अवतार का यह प्रकट होना केवल एक दैवी चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी भी सीमित परिभाषा में बंधे नहीं होते। वे हर उस रूप में प्रकट हो सकते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो। नरसिंह भगवान ने संध्या समय—जो न दिन था और न रात—हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर—जो न धरती थी और न आकाश—लिटाकर अपने नाखूनों से—जो न अस्त्र थे और न शस्त्र—उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त को बनाए रखते हुए न्याय की स्थापना की।

हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र स्वरूप समस्त सृष्टि के लिए भय का कारण बन गया। देवता, ब्रह्मा और यहां तक कि देवी लक्ष्मी भी उन्हें शांत नहीं कर सकीं। अंततः प्रह्लाद ने आगे बढ़कर उनके चरणों को स्पर्श किया और अपनी निष्कलंक भक्ति के माध्यम से उन्हें शांत किया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि भक्ति में वह शक्ति है, जो ईश्वर के सबसे उग्र रूप को भी शांत कर सकती है।

प्रह्लाद को आशीर्वाद देते हुए नरसिंह भगवान ने उन्हें राज्य सौंपा और धर्मपूर्वक शासन करने का निर्देश दिया। यह केवल एक व्यक्ति की विजय नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय थी। यह घटना यह भी बताती है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है, जो भक्ति, विनम्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो।

नरसिंह अवतार की यह कथा हमें कई स्तरों पर प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यह हमें यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और आस्था किसी भी विपत्ति से बड़ी होती है। साथ ही, यह संदेश भी देती है कि ईश्वर का न्याय सदैव सटीक और समयानुकूल होता है।

आज के आधुनिक युग में, जब समाज अनेक प्रकार के नैतिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा है, यह कथा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हिरण्यकश्यप का अहंकार आज भी विभिन्न रूपों में हमारे समाज में मौजूद है—कभी सत्ता के रूप में, कभी धन के रूप में, तो कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप में। वहीं, प्रह्लाद की भक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

अंततः, नरसिंह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है, जो हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है। यह विश्वास ही मानव जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, जो हमें अंधकार में भी प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है और यह याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पांच राज्यों की किस्मत आज तय: सियासत के रण में कौन करेगा विजय पताका फहराने का दावा

देश की लोकतांत्रिक यात्रा में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे समाज की सामूहिक चेतना, उम्मीदों और आकांक्षाओं का आईना भी होते हैं। आज जब पांच राज्यों—तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल—के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने जा रहे हैं, तब पूरे देश की निगाहें इस महत्त्वपूर्ण क्षण पर टिकी हुई हैं। यह केवल क्षेत्रीय राजनीति का प्रश्न नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और भविष्य के संकेत भी इन्हीं परिणामों में छिपे होते हैं। सुबह आठ बजे से शुरू होने वाली मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे राजनीतिक समीकरणों की परतें खुलती जाएंगी और यह स्पष्ट होगा कि जनता ने किसे अपना विश्वास सौंपा है और किसे नकार दिया है।

इन चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इनमें अभूतपूर्व उत्साह और भागीदारी देखने को मिली। कई राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो इस बात का संकेत है कि मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक और सक्रिय हो चुके हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जब जनता बढ़-चढ़कर मतदान करती है, तो उसका संदेश स्पष्ट होता है कि वह अपनी सरकारों से जवाबदेही चाहती है और अपने अधिकारों के प्रति सजग है। यही कारण है कि इन चुनावों को केवल एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां का चुनाव सबसे अधिक चर्चा में रहा है। एक ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस है, जिसने पिछले कई वर्षों से राज्य की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो इस बार पूरे दमखम के साथ पहली बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। यहां का मुकाबला केवल दो दलों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और विकास मॉडलों के बीच भी है। रिकॉर्ड मतदान ने इस मुकाबले को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के अलग-अलग रुझान, महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी और विभिन्न सामाजिक वर्गों की प्राथमिकताएं इस चुनाव को बहुआयामी बना देती हैं। ऐसे में यह देखना बेहद रोचक होगा कि जनता ने किस पक्ष को अधिक समर्थन दिया है।

असम में भी चुनावी माहौल कम रोचक नहीं रहा। यहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की लोकप्रियता, सरकार की विकास योजनाएं और संगठनात्मक मजबूती इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ मैदान में रहा और उसने स्थानीय मुद्दों को जोर-शोर से उठाया। असम के परिणाम यह तय करेंगे कि क्या राज्य में सत्ता का सिलसिला जारी रहेगा या जनता बदलाव का विकल्प चुनेगी।

केरल की राजनीति हमेशा से विचारधारात्मक रही है और यहां का चुनाव भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। केरल में लंबे समय से सत्ता परिवर्तन का एक ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार वाम मोर्चा अपनी नीतियों और कामकाज के आधार पर सत्ता में बने रहने का दावा कर रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन जनता के असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है। यहां भाजपा भी अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के प्रयास में है, हालांकि उसकी स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

तमिलनाडु में चुनावी परिदृश्य अलग ही रंग लिए हुए है। यहां द्रविड़ राजनीति का प्रभाव हमेशा से रहा है और इस बार भी मुकाबला मुख्य रूप से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच ही केंद्रित रहा है। हालांकि, इस बार कुछ नई राजनीतिक ताकतों और क्षेत्रीय दलों के उभरने से समीकरण थोड़े जटिल हो गए हैं। अभिनेता विजय की पार्टी और अन्य नए चेहरों की मौजूदगी ने चुनाव को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। तमिलनाडु के परिणाम यह तय करेंगे कि क्या पारंपरिक दल अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या नई ताकतें राजनीति में बदलाव का संकेत देंगी।

पुडुचेरी भले ही एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहां के चुनावी परिणाम भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। यहां गठबंधन की राजनीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और परिणाम यह तय करेंगे कि किस गठबंधन को जनता का समर्थन मिला है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिणाम अक्सर बड़े राजनीतिक संकेत देते हैं, क्योंकि वे यह दिखाते हैं कि स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय राजनीति के बीच संतुलन किस प्रकार बन रहा है।

इन सभी राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम की निगरानी और मतगणना केंद्रों पर सख्त नियम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठे। डाक मतपत्रों की गिनती से शुरुआत और उसके बाद ईवीएम की गिनती एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का हिस्सा है, जो धीरे-धीरे अंतिम परिणाम की ओर बढ़ती है।

इन चुनावों के परिणाम केवल राज्यों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। यदि सत्ताधारी दलों को जीत मिलती है, तो यह उनकी नीतियों और कामकाज पर जनता की मुहर मानी जाएगी। वहीं यदि विपक्ष को सफलता मिलती है, तो यह संकेत होगा कि जनता बदलाव चाहती है और सरकारों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, ये परिणाम आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी एक संकेतक की भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा, इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों की प्राथमिकताओं को उजागर किया है। युवा मतदाता रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण मतदाता कृषि और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि वे अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय निर्णयकर्ता बन चुकी हैं। यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक है, क्योंकि यह समाज के हर वर्ग की आवाज को मजबूत बनाता है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान उठाए गए मुद्दे—जैसे महंगाई, बेरोजगारी, विकास, सामाजिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था—अब परिणामों के माध्यम से अपनी दिशा तय करेंगे। जनता ने अपने मत के माध्यम से जो संदेश दिया है, वह सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होगा। यह आवश्यक है कि जो भी दल सत्ता में आए, वह इन मुद्दों को गंभीरता से ले और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करे। आज का दिन केवल परिणामों का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी है। राजनीतिक दलों के लिए यह समय है कि वे अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और समझें कि जनता ने उन्हें क्यों स्वीकार या अस्वीकार किया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इसमें हर चुनाव एक नया अवसर लेकर आता है—सुधार का, बदलाव का और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि इन पांच राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति में एक नई दिशा तय करेंगे। कहीं सत्ता की वापसी होगी, तो कहीं बदलाव की बयार चलेगी। कहीं पुरानी नीतियों को समर्थन मिलेगा, तो कहीं नए प्रयोगों को मौका मिलेगा। अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी हैं, जहां हर रुझान एक कहानी कहेगा और हर परिणाम एक संदेश देगा। यही लोकतंत्र की असली ताकत है—जनता का फैसला, जो अंतिम और सर्वोपरि होता है।

सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा और साहसिक रेस्क्यू: टंकी पर फंसे बच्चों को एयरफोर्स ने बचाया

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक जर्जर पानी की टंकी पर हुआ हादसा जहां एक ओर गहरी पीड़ा छोड़ गया, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और वायु सेना के समन्वित प्रयासों ने एक बड़े संकट को टाल दिया। कांशीराम कॉलोनी में स्थित करीब 30 साल पुरानी ओवरहेड टंकी पर चढ़े पांच बच्चों में से एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए और टंकी पर फंसे दो बच्चों को भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित नीचे उतारा गया। घटना शनिवार की बताई जा रही है, जब इलाके के पांच किशोर खेल-खेल में टंकी पर चढ़ गए थे। नीचे उतरते समय अचानक जर्जर सीढ़ी भरभराकर गिर गई, जिससे तीन बच्चे सीधे नीचे आ गिरे। हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों—गोलू (12), सनी (14) और सिद्धार्थ (10)—को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। अन्य दो बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच, टंकी के ऊपरी हिस्से में पवन (14) और शाबान (12) फंसे रह गए। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा था और स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। प्रशासन ने पहले वैकल्पिक सीढ़ी या रास्ता बनाकर उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन बारिश और संरचना की खराब हालत के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। समय बीतने के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे ऊंचाई पर बिना सुरक्षा के फंसे हुए थे।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल उच्च स्तर पर संपर्क साधा। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने मुख्यमंत्री कार्यालय और आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय कर वायु सेना की मदद मांगी। इसके बाद गोरखपुर से भारतीय वायु सेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर मौके पर भेजा गया।

रातभर दोनों बच्चे टंकी पर फंसे रहे, जिससे उनके परिजनों और स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई। रविवार सुबह करीब 5:20 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यह अभियान बेहद सावधानी और सटीकता के साथ चलाया गया, क्योंकि जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। वायु सेना के जवानों ने जोखिम उठाते हुए दोनों बच्चों को एक-एक कर सुरक्षित नीचे उतारा।

इस पूरे अभियान के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और राहत टीम मौके पर मौजूद रही और हर स्तर पर समन्वय बनाए रखा गया। अंततः यह चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया।

यह घटना जहां एक ओर प्रशासन की तत्परता और वायु सेना की दक्षता को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर जर्जर सार्वजनिक ढांचों की अनदेखी पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह टंकी लंबे समय से खराब स्थिति में थी, लेकिन इसकी मरम्मत या सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिद्धार्थनगर की यह घटना एक चेतावनी भी है कि सार्वजनिक स्थानों की नियमित जांच और रखरखाव कितना आवश्यक है।

सूरत में स्वास्थ्य जागरूकता की मिसाल: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सातवां निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर सफल

सूरत शहर में सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता का एक प्रेरक उदाहरण अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में देखने को मिला, जहां सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान लगातार प्रभावी रूप से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2026 से शुरू हुई इस पहल के तहत रविवार, 3 मई 2026 को सातवां निःशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाई।

यह शिविर अग्रवाल समाज ट्रस्ट के तत्वावधान में श्याम भक्त मित्र मंडल के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक विधि से हुई, जहां रामप्रसाद अग्रवाल, राज कुमार अग्रवाल, श्याम खेतान, गोवर्धन मोदी तथा मंडल के पदाधिकारियों डॉ. प्रमोद पिपरालीवाले, विनोद गुप्ता, संजय जगनानी, संजीव खेतान और भूपेंद्र अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

शिविर के दौरान हेल्थ सेंटर के चेयरमैन श्रवण अग्रवाल और प्रभारी विनोद चिड़ावावाला के नेतृत्व में पूरी टीम ने व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संभाला। उनके साथ सुनील गोयल, अजय विदावतका, प्रदीप गाड़िया, शिवरतन जगनानी, राकेश बजावा, विमल झांझरिया, प्रभात जालान, जगमोहन जालान, संपत पोदार, पिंटू चिरानिया और अशोक केडिया जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे आयोजन सुव्यवस्थित और सफल रहा।

इस शिविर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई गई, जो महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वैक्सीन लगवाई, जो इस बात का संकेत है कि अब समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है।

आयोजकों ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं के बीच एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है, लेकिन समय पर टीकाकरण और नियमित जांच के माध्यम से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं तक इस जीवनरक्षक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह पूरी तरह निःशुल्क है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं भी बिना किसी झिझक के इसमें भाग ले सकती हैं। सामाजिक संगठनों और ट्रस्ट द्वारा इस तरह की पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा भी तय करती है।

कार्यक्रम के दौरान यह भी संदेश दिया गया कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ आवश्यक टीकाकरण भी कराना चाहिए। जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

अंततः, अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में आयोजित यह सातवां वैक्सीनेशन शिविर केवल एक चिकित्सा कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर सामने आया। यह पहल दर्शाती है कि जब समाज और संगठन मिलकर काम करते हैं, तो स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी बड़े बदलाव संभव हैं। आने वाले समय में इस अभियान के और विस्तार की उम्मीद है, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिल सके।

ओलपाड से उठी हरित क्रांति की नई पुकार: 'बैक टू नेचर' के संदेश के साथ प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान

सूरत जिले के ओलपाड तालुका के जिनोद गांव में आयोजित नेचुरल एग्रीकल्चर सेमिनार केवल एक कृषि कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह खेती की बदलती दिशा, किसानों की चिंताओं और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी और समाधान दोनों के रूप में सामने आया। आचार्य देवव्रत की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया, जहां उन्होंने किसानों को 'बैक टू नेचर' का संदेश देते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाने का जोरदार आह्वान किया।

पुरुषोत्तम जिन फार्मर्स कंपाउंड में आयोजित इस सेमिनार में बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि इसमें एक आत्मीय संवाद की झलक दिखाई दी, जहां खेती के वर्तमान संकट और उसके समाधान पर खुलकर चर्चा हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज की केमिकल आधारित खेती केवल उत्पादन का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग जमीन की उर्वरता को धीरे-धीरे खत्म कर रहा है। खेतों की मिट्टी, जो कभी जीवंत और पोषक तत्वों से भरपूर हुआ करती थी, आज धीरे-धीरे बंजर होने की ओर बढ़ रही है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यही रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक पहुंच रहे हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। आचार्य देवव्रत ने एक शोध का उल्लेख करते हुए बताया कि हाल ही में किए गए परीक्षणों में माताओं के दूध में भी रसायनों के अंश पाए गए हैं। उन्होंने इसे केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी बताया। उनके अनुसार, यदि आज भी हम नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे केवल उत्पादन बढ़ाने के पीछे न भागें, बल्कि ऐसी खेती अपनाएं जो मानव और प्रकृति दोनों के लिए सुरक्षित हो।

अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो धारणा बनी हुई है कि इसमें उत्पादन कम होता है, वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़े स्तर पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वहां बिना रासायनिक उर्वरकों के भी अच्छी उपज प्राप्त हो रही है। साथ ही लागत भी काफी कम हो जाती है, जिससे किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि होती है।

उन्होंने किसानों को व्यावहारिक सुझाव देते हुए कहा कि वे एकदम से पूरी खेती को बदलने की बजाय शुरुआत में अपनी जमीन के छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती का प्रयोग करें। जब उन्हें इसके परिणाम दिखने लगें, तब धीरे-धीरे इसका विस्तार करें। इस क्रमिक बदलाव से न केवल जोखिम कम होगा, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

राज्यपाल ने देसी गाय आधारित खेती के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि देसी गाय केवल दूध का स्रोत नहीं है, बल्कि प्राकृतिक खेती की आधारशिला है। गोबर और गोमूत्र से तैयार जैविक खाद और कीटनाशक न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, बल्कि जल संरक्षण और जैव विविधता को भी सुदृढ़ करते हैं। उनके अनुसार, यह खेती केवल कृषि पद्धति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की सीख देता है।

सेमिनार के दौरान ATMA (आत्मा) कार्यालय के सहयोग से प्राकृतिक खेती से जुड़े विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉलों पर किसानों को जैविक उत्पादों, तकनीकों और उपकरणों की जानकारी दी गई। राज्यपाल ने स्वयं इन स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और समस्याएं जानीं। यह संवाद कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जहां किसानों को अपनी बात रखने और समाधान प्राप्त करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम में मुकेश दलाल और मुकेश पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार, वैज्ञानिक और किसान मिलकर इस दिशा में कार्य करें, तो कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन संभव है। इस सेमिनार में यह भी स्पष्ट हुआ कि आज का किसान केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह अपनी जमीन, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को लेकर भी सजग हो रहा है। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता यह रुझान इसी जागरूकता का परिणाम है।

अंततः, ओलपाड का यह आयोजन सूरत जिले में प्राकृतिक खेती के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह केवल एक सेमिनार नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत जैसा प्रतीत हुआ, जिसमें किसानों को टिकाऊ, सस्ती और स्वास्थ्यप्रद खेती की ओर प्रेरित किया गया। 'बैक टू नेचर' का संदेश अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बनता जा रहा है, जिसे अपनाकर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

वैश्विक दबावों के बीच यूनिलीवर की रणनीतिक बढ़त : आपूर्ति संकट में अवसर तलाशती कंपनी

वैश्विक अर्थव्यवस्था के अस्थिर दौर में जहां अधिकांश कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं, बढ़ती लागत और मांग में अनिश्चितता से जूझ रही हैं, वहीं Unilever ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को अवसर में बदलने की रणनीति अपनाई है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी फर्नांडो फर्नांडीज के हालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब केवल संकट से निपटने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए इन परिस्थितियों का उपयोग भी कर रही हैं।

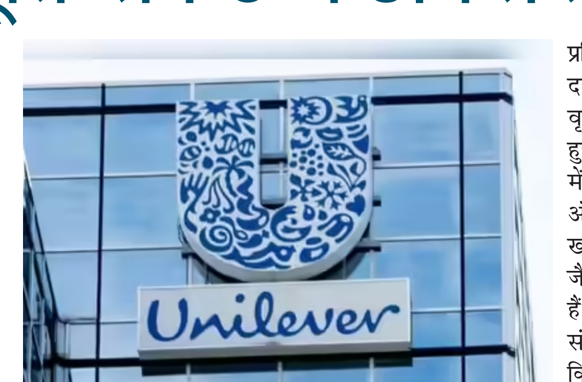

फर्नांडीज ने संकेत दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर पैकेजिंग लागत पर पड़ा है। प्लास्टिक और अन्य पैकेजिंग सामग्री, जो तेल आधारित उत्पादों से निर्मित होती हैं, उनकी कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रभाव विशेष रूप से उन स्थानीय कंपनियों पर अधिक पड़ा है, जिनकी आपूर्ति व्यवस्था सीमित और वित्तीय संसाधन अपेक्षाकृत कमजोर हैं। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे उभरते बाजारों में यह दबाव और अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।

ऐसी स्थिति में यूनिलीवर ने अपनी बहुध्रुवीय आपूर्ति श्रृंखला (multi-polar supply chain) की मजबूती का लाभ उठाया है। कंपनी के पास विभिन्न क्षेत्रों में फैले उत्पादन केंद्र, विविध आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन है, जिससे वह किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर भी अपने संचालन को संतुलित रख सकती है। यही कारण है कि जहां कई छोटी और मध्यम कंपनियां आपूर्ति और नकदी संकट से जूझ रही हैं, वहीं यूनिलीवर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की स्थिति में है।

भारत में यूनिलीवर की सहायक कंपनी Hindustan Unilever Limited (HUL) ने इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है। कंपनी ने घरेलू देखभाल (होम केयर) श्रेणी, विशेषकर लॉन्ड्री उत्पादों में अपनी हिस्सेदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में लॉन्ड्री पाउडर श्रेणी में कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी दर्ज की, जो इस बात का संकेत है कि उपभोक्ता विश्वास और वितरण नेटवर्क दोनों ही मजबूत बने हुए हैं।

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवास के अनुसार, जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान बिक्री की मात्रा में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब बाजार में लागत दबाव और उपभोक्ता खर्च में सावधानी जैसे कारक मौजूद हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि यूनिलीवर ने मूल्य निर्धारण (pricing) और मांग प्रबंधन (demand management) के बीच संतुलन बनाने में सफलता हासिल की है। विशेष रूप से तरल डिटर्जेंट (liquid detergent) जैसे उभरते सेगमेंट में कंपनी की आक्रामक रणनीति ने उसे प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ने में मदद की है। बदलती उपभोक्ता आदतों और शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के चलते इस श्रेणी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यूनिलीवर ने इस ट्रेंड को समय रहते पहचानकर अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को उसी अनुरूप ढाला है, जिससे उसे अतिरिक्त लाभ मिला है।

फर्नांडीज ने यह भी संकेत दिया कि वर्तमान मुद्रास्फीति (inflation) की स्थिति, जो आमतौर पर कंपनियों के लिए चुनौती मानी जाती है, घरेलू देखभाल खंड में यूनिलीवर के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। इसका कारण यह है कि इस श्रेणी के उत्पाद दैनिक आवश्यकता से जुड़े होते हैं, जिनकी मांग अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। ऐसे में कीमतों में सीमित वृद्धि भी कंपनी के राजस्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

हालांकि, यह परिदृश्य पूरी तरह एकतरफा नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां, कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारक अभी भी जोखिम बने हुए हैं। लेकिन यूनिलीवर की रणनीति यह दर्शाती है कि जिन कंपनियों के पास मजबूत बुनियादी ढांचा, विविध आपूर्ति स्रोत और लचीली कारोबारी नीतियां होती हैं, वे ऐसे संकटों से न केवल उबर सकती हैं, बल्कि उनमें अवसर भी तलाश सकती हैं।

भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण बाजार में यह प्रतिस्पर्धा और भी रोचक हो जाती है, जहां एक ओर स्थानीय कंपनियां अपने सीमित संसाधनों के साथ संघर्ष कर रही हैं, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वैश्विक अनुभव और संसाधनों के दम पर बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय कंपनियां इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं और क्या वे भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाती हैं या नहीं।

कुल मिलाकर, यूनिलीवर का यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में केवल उत्पाद की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, लागत प्रबंधन और बाजार की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। यही वे कारक हैं, जो किसी कंपनी को संकट के दौर में भी आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं।

सूरत में उद्यमियों की हुंकार: 'उद्योग से राष्ट्र निर्माण' का संकल्प, MSME को वैश्विक ताकत बनाने का आह्वान

सूरत में आयोजित उद्यमी सम्मेलन–2026 ने केवल एक औपचारिक आयोजन का स्वरूप नहीं लिया, बल्कि यह देश के औद्योगिक भविष्य, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा। लघु उद्योग भारती (सूरत जिला) द्वारा श्री नरेंद्र पंचासरा भवन में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में उद्यमियों, उद्योगपतियों और सामाजिक प्रतिनिधियों की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि MSME सेक्टर आज भी देश की आर्थिक रीढ़ बना हुआ है और उसकी भूमिका आने वाले समय में और अधिक निर्णायक होने वाली है।

कार्यक्रम की शुरुआत उत्साह और गरिमा के साथ हुई, जहां मुख्य अतिथियों के रूप में प्रकाशचंद्र गुप्ता, सांवर प्रसाद बुधिया, दशरथ शेखावत, जे.बी. दवे और बलदेवभाई प्रजापत उपस्थित रहे। इन सभी ने अपने-अपने संबोधनों में उद्योग, समाज और राष्ट्र के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया और उद्यमियों को देश निर्माण में अपनी भूमिका को और सशक्त करने का आह्वान किया।

अपने प्रभावशाली उद्बोधन में प्रकाशचंद्र गुप्ता ने भारत की ऐतिहासिक औद्योगिक समृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय भारत "सोने की चिड़िया" इसलिए था क्योंकि यहां के लघु उद्योग आत्मनिर्भर थे और हर हाथ को काम उपलब्ध कराते थे। उन्होंने कहा कि आज भी वही क्षमता देश में मौजूद है, बस आवश्यकता है उसे आधुनिक तकनीक और सही दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित करने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 33 वर्षों से लघु उद्योग भारती MSME सेक्टर की आवाज बनकर न केवल नीतिगत स्तर पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी उद्योगों को मजबूती देने का कार्य कर रही है।

उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार सृजन की होगी और इसमें MSME सेक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। "सर्वे भवन्तु सुखिनः" के मूल मंत्र को अपनाते हुए उन्होंने उद्योगों में नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, यदि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, तो लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना ही होगा।

सम्मेलन में तकनीक और नवाचार को भी विशेष महत्व दिया गया। प्रकाशचंद्र गुप्ता ने उद्यमियों को सलाह दी कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डिजिटल तकनीकों को अपनाकर अपने उद्योगों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि भारत आज सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरण जैसे उन्नत क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि देश अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक और नवप्रवर्तक की भूमिका में भी आगे बढ़ रहा है।

सूरत अध्यक्ष रामावतार पारीक ने संगठन की स्थानीय गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रवासी और जरूरतमंद लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि उद्योगों को भी कुशल श्रमिक उपलब्ध होंगे।

गुजरात अध्यक्ष ईश्वरभाई पटेल ने संगठन की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्यभर में उद्योगों को जोड़ने और उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं वजूभाई वगासिया ने आगामी अक्टूबर में आयोजित होने वाले आईआरएफ कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसे उद्योग जगत के लिए एक बड़ा अवसर बताया गया।

सम्मेलन के दौरान पांच उद्यमियों—वामपुम सिंटेक्स, गौरी पुत्र, देवश्री, ओल्ज़िन और युग फैशन—को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए "उत्कृष्ट उद्यमी" सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनकी उपलब्धियों की पहचान था, बल्कि अन्य उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना।

संगठन विस्तार के तहत भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिसमें हंसराज जैन को संभाग उपाध्यक्ष तथा राजेंद्र चौधरी और विजय मांगुकिया को संभाग मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए।

कार्यक्रम में अनेक प्रमुख सदस्य जैसे विनोद सारस्वत, गणपत भाटी, श्याम तावनिया, हरीओम स्वामी, अशोक शाह, विजय चौमाल, बाबूभाई पालीवाल, गोपाल पारीक, दामोदर कड़ेल, शिवजी पारीक, साजन महर्षि, नंदकिशोर शर्मा, कामना खंडेलवाल और चंचल वाचानी की उपस्थिति ने आयोजन को और अधिक प्रभावशाली बना दिया।

अंत में महामंत्री सतीश सवानी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र राजावत ने कुशलता से किया। सम्मेलन का समापन सामूहिक भोज के साथ हुआ, जहां सभी ने अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान किया।

कुल मिलाकर, सूरत का यह उद्यमी सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संदेश बनकर उभरा—कि यदि उद्योग सशक्त होंगे, तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। MSME सेक्टर को नई दिशा, तकनीक और अवसरों से जोड़कर भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प इस मंच से स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

शेयर बाजार में हल्की बढ़त, चार बड़ी कंपनियों की संपत्ति में 2.20 लाख करोड़ का उछाल

जीएनएस)। नई दिल्ली में पिछले छोटे कारोबारी सप्ताह के दौरान शेयर बाजार में सीमित लेकिन सकारात्मक रुझान देखने को मिला। छुट्टियों के कारण कम कारोबारी सत्र रहे इस सप्ताह में बीएसई सेंसेक्स में 249.29 अंकों यानी 0.32 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, पूरे सप्ताह बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा और निवेशकों की धारणा वैश्विक व घरेलू संकेतों के बीच संतुलित बनी रही।

इस अवधि में देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार कंपनियों ने मिलकर लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण जोड़ लिया, जिससे इन कंपनियों के निवेशकों की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सबसे अधिक फायदा देश की सबसे बड़ी कंपनी को हुआ, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस सप्ताह सबसे मजबूत प्रदर्शन किया।

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस हल्की बढ़त के पीछे कई मिश्रित कारक जिम्मेदार रहे। अजीत मिश्रा के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव में कुछ कमी और कुछ कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों ने शुरुआत में बाजार को सहारा दिया। लेकिन बाद में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ने बाजार की रफ्तार को सीमित कर दिया। इस सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ-साथ कुछ अन्य बड़ी कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। भारती एयरटेल, टीसीएस और बजाज फाइनेंस के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जिससे इनके बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई। खासकर टेलीकॉम और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेशकों की रुचि बनी रही, जिसका सीधा असर इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर पड़ा।

आंकड़ों के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण इस सप्ताह 1,39,655.8 करोड़ रुपये बढ़कर 19,36,303.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो इसे एक बार फिर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाए रखता है। वहीं भारती एयरटेल का मार्केट कैप 43,503.51 करोड़ रुपये बढ़कर 11,49,222.13 करोड़ रुपये हो गया। टीसीएस और बजाज फाइनेंस ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और उनके बाजार मूल्य में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर, बैंकिंग और कुछ प्रमुख ब्लूचिप कंपनियों में गिरावट का रुख देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी जैसी कंपनियों के संयुक्त बाजार मूल्य में लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग सेक्टर में यह कमजोरी मुख्य रूप से मुनाफावसूली और वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के कारण देखी गई।

रेल सुरक्षा बल की तत्परता से यात्रा के दौरान छूटा महंगा लैपटॉप एवं अन्य सामान सुरक्षित वापस मिला

जीएनएस)। भारतीय रेल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल कर्मी ने एक बार फिर तत्परता का परिचय देते हुए तेजस एक्सप्रेस में मुंबई से नई दिल्ली यात्रा कर रहे यात्री के छूटे महंगे लैपटॉप सहित लगभग 3.5 लाख रूपए का सामान यात्री को सफलतापूर्वक लौटाया। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 29 अप्रैल 2026 को ट्रेन संख्या 12951 तेजस एक्सप्रेस के कोच संख्या B-9 में मुंबई से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे श्री सूरज झा सूरत स्टेशन पर खाने का सामान लेने उतरे। वापिस ट्रेन पर आते समय गाड़ी के दरवाजे बंद हो गए और गाड़ी रवाना हो गई। जिस कारण सूरज जी का एक ग्रीन कलर ट्राली बैग व लैपटॉप बैग उक्त ट्रेन में छूट गए।

यात्री द्वारा तत्काल रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर इसकी सूचना दी गई। छूट जाने की सूचना प्राप्त होते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) SIPF निशा मीणा साथ में स्टाफ द्वारा वडोदरा स्टेशन पर खड़ी मुंबई - नई दिल्ली तेजस ट्रेन के कोच संख्या B-9 की जांच के दौरान सीट पर सुरक्षित अवस्था में सामान प्राप्त हुआ। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया एक ग्रीन कलर का ट्राली बैग व लैपटॉप बैग सामान मिला जिसको पोस्ट पर लाकर जमा किया।

यात्री द्वारा बताए गए विवरण से सामान का मिलान करने तथा आवश्यक सत्यापन के उपरांत उप निरीक्षक निशा मीणा द्वारा उक्त तीन लैपटॉप, हेडफोन, चार्जर व कपड़े होना बताया। जिसकी कीमत लगभग 3 .5 लाख रूपए थी, जिसे संबंधित यात्री सूरज झा जी को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया। अपने लैपटॉप सुरक्षित वापस मिलने पर यात्री श्री सूरज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा संचालित रेल मदद 139 हेल्पलाइन की त्वरित एवं प्रभावी सेवा की सराहना की। साथ ही उन्होंने आरपीएफ वडोदरा पोस्ट की तत्परता तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा की।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी वस्तु के छूट जाने या आपात स्थिति में तुरंत रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा 'ऑपरेशन अमानत' यात्रियों की खोई हुई वस्तुओं को खोजकर उन्हें सुरक्षित लौटाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य कर रहा है, जिससे यात्रियों में रेलवे के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ हो रही है।

हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल, अब खुलने लगी परतें, घर, फ्लैट, दुकान खरीदारों के सपनों पर खतरे की घंटी!

जीएनएस)। गुजरात के वलसाड जिले तथा पड़ोसी संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव क्षेत्र में बीते वर्षों में तेजी से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और टाउनशिपों का विस्तार हुआ है। हजारों परिवारों ने अपनी जीवनभर की कमाई, बैंक लोन, गहने बेचकर या वर्षों की बचत लगाकर घर, फ्लैट और दुकानें खरीदीं। अधिकांश लोगों ने यह मानकर निवेश किया कि जिस बिल्डिंग में वे प्रवेश कर रहे हैं, वह कानूनी रूप से सुरक्षित, नियमों के अनुरूप और भविष्य के लिए भरोसेमंद होगी।

लेकिन अब अनेक स्तरों पर ऐसी जानकारियाँ सामने आ रही हैं, जिन्होंने इस विश्वास पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर यह शिकायतें और आशंकाएँ उठ रही हैं कि कुछ स्थानों पर निर्माण स्वीकृत नक्शे से अलग हुआ, कहीं रोड मार्जिन और खुली जगहों का पालन नहीं किया गया, कहीं बरसाती नालों, जल निकासी मार्गों या सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ की गई, कहीं फायर सेफ्टी व्यवस्था अधूरी है, तो कहीं भूमि अभिलेख, सरकारी पोर्टल और खरीदारों को दिए गए दस्तावेजों में अंतर बताया जा रहा है। यदि इन बातों में सत्यता है, तो मामला केवल निर्माण त्रुटि का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा का है।

सबसे बड़ा प्रश्न – खामियाजा कौन भुगतेगा?

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि यदि किसी प्रोजेक्ट में भविष्य में अनियमितता सिद्ध होती है, यदि कोई विभाग कार्रवाई करता है, यदि अदालत में विवाद उठता है, यदि अवैध निर्माण हटाने का आदेश आता है, यदि फायर सेफ्टी या संरचनात्मक कमी सामने आती है, यदि जल निकासी बाधित होने से सार्वजनिक समस्या पैदा होती है, या यदि भूमि रिकॉर्ड विवादित निकलता है—तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा?

उत्तर सरल है—उस खरीदार पर, जिसने ईमानदारी से पैसा देकर संपत्ति खरीदी। बिल्डर तो अधिकांश मामलों में परियोजना बेचकर आगे बढ़ चुका होता है। लाभ ले चुका होता है। नई परियोजनाओं में प्रवेश कर चुका होता है। लेकिन खरीदार उसी भवन में रहता है, EMI भरता है, परिवार बसाता है, बच्चों का भविष्य जोड़ता है और उसी पते पर अपनी पूरी जिंदगी की योजना बनाता है।

यानी लाभ किसी और का, जोखिम किसी और के सिर।

क्या केवल स्वीकृति मिल जाना पर्याप्त है? आम नागरिक अक्सर यह मान लेते हैं कि यदि बिल्डिंग बन गई, बिजली-पानी आ गया, पजेशन मिल गया, रजिस्ट्री हो गई और सरकारी कागज मौजूद हैं, तो सब कुछ सही होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कागजी स्वीकृति हमेशा पर्याप्त नहीं होती।

यदि स्वीकृति गलत जानकारी देकर ली गई हो, यदि वास्तविक निर्माण स्वीकृत प्लान से अलग हो, यदि निरीक्षण में लापरवाही हुई हो, यदि प्रभाव या भ्रष्टाचार से नियमों की अनदेखी हुई हो—तो भविष्य में वही फाइलें विवाद का कारण बन सकती हैं।

यानी आज जो दस्तावेज सुरक्षित लग रहे हैं, वही कल जांच का विषय बन सकते हैं।

शिकायतें और भी गंभीर हैं

कुछ मामलों में यह भी कहा जा रहा है कि भूमि विवाद लंबित रहते हुए विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ गई, मुकदमे चलते रहे और दूसरी ओर निर्माण भी हो गया। कुछ स्थानों पर प्राकृतिक जल निकासी तंत्र के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। कहीं यह सवाल उठ रहे हैं कि जो सर्वे नंबर सरकारी रिकॉर्ड में है, वही खरीदार के दस्तावेज में क्यों नहीं दिखता। यदि ऐसी स्थितियाँ सही पाई जाती हैं, तो यह साधारण तकनीकी गलती नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक और कानूनी विषय है।

खरीदार क्यों नहीं समझ पाता?

एक आम परिवार घर खरीदते समय बिल्डर के ब्रॉशर, मॉडल फ्लैट, लोकेशन, कीमत, EMI योजना और पजेशन डेट पर ध्यान देता है। वह शायद ही यह जांच पाता है कि स्वीकृत प्लान क्या है, सेटबैक कितना होना चाहिए, फायर सिस्टम पूर्ण है या नहीं, भूमि रिकॉर्ड क्या कहते हैं, या निर्माण सभी शर्तों के अनुसार हुआ है या नहीं।

कारण भी स्पष्ट है—आम नागरिक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर या कानूनी विशेषज्ञ नहीं होता। वह विश्वास के आधार पर खरीदता है। और यदि यही विश्वास टूटे, तो सबसे बड़ी चोट भी उसी को लगती है।

समय रहते जागना जरूरी

विशेषज्ञ मानते हैं कि खरीदारों को अपने प्रोजेक्ट्स के मूल दस्तावेज, स्वीकृत नक्शा, Completion Certificate, Occupancy Certificate, फायर NOC, भूमि रिकॉर्ड, सोसाइटी दस्तावेज और कॉमन एरिया स्थिति की जानकारी समय रहते प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि वर्षों बाद समस्या सामने आने पर जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है। समय बदलता है, कंपनियाँ बदलती हैं, मालिक बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं, रिकॉर्ड गायब होते हैं, और कई बार जिम्मेदार लोग उपलब्ध भी नहीं रहते। तब पीड़ित वही बनता है जिसने जीवनभर की कमाई लगाई होती है।

अब सवाल जनता का है

यदि खरीदार ने पूरा भुगतान किया, स्टाम्प ड्यूटी दी, टैक्स दिया, बैंक ब्याज भरा और परिवार का भविष्य दांव पर लगाया—तो क्या उसे नियमसम्मत, सुरक्षित और निर्विवाद संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए? यह प्रश्न अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा। यह सार्वजनिक हित, शहरी नियोजन, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों का प्रश्न बन चुका है। क्योंकि यह केवल इमारतों की कहानी नहीं—यह हजारों परिवारों के सपनों, अधिकारों और भविष्य का मामला है।

कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि होगी, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव बढ़ेगा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश भर में एक ही दिन में व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी के साथ, दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपये तक पहुंच गई है। लगातार तीसरे महीने कीमत में बढ़ोतरी होने से, इसका असर होटलों, ढाबों और छोटे व्यापारियों पर पड़ना तय है। इससे चाय की दुकानों, बेकरी और मिठाई की दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के साथ-साथ घरेलू खर्चों पर भी असर पड़ेगा। और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहले गैस पर हमला, अब अगला हमला पेट्रोल-डीजल पर होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में भी 261 रुपये की बढ़ोतरी की है। छोटे सिलेंडरों की बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर गरीबों और कामकाजी वर्ग पर पड़ेगा। हालांकि, घरेलू एलपीजी, पेट्रोल, डीजल

और केरोसिन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

तेल कंपनियों (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) ने शुक्रवार को इस मूल्य संशोधन की घोषणा की। यह वृद्धि केवल व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों और पांच किलोग्राम के सिलेंडरों पर लागू होगी। घरेलू एलपीजी (सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर) की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इस मूल्य वृद्धि से रेस्तरां, खानपान सेवाओं और छोटे व्यवसायों के मुनाफे में कमी आने की आशंका है। इनमें से कई व्यवसाय अपने दैनिक कार्यों के लिए व्यावसायिक एलपीजी पर निर्भर हैं। मुंबई और कोलकाता जैसे कई महानगरों में बढ़ते किराए और मजदूरी के कारण रेस्तरां मालिकों के मुनाफे पर हाल के दिनों में दबाव बना हुआ है, जहां मुनाफा कम होने के कारण होटल मालिकों को अपने ग्राहकों पर इसका असर न पड़े, इसलिए कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करना होगा।

शिक्षा के निजीकरण से फीस बढ़ी है और गुणवत्ता घटी है; सरकारी नीति पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात समेत पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण ने गुजरात की महाजन संस्कृति को नष्ट कर दिया है। एक समय था जब उद्योगपति अपने मुनाफे का इस्तेमाल समाज के हित में शिक्षण संस्थान खोलने में करते थे। अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी और गुजरात लॉ सोसाइटी इसके सशक्त उदाहरण थे। आज, निरमा के करसनदास पटेल या मुकेश अंबानी ऐसे कॉलेज या विश्वविद्यालय खोल रहे हैं जिनसे उन्हें सिर्फ मुनाफा मिलता है? क्या वे शिक्षा से भी मुनाफा कमाना चाहते हैं? अब तो छोटे उद्योगपति भी इस धंधे में उतर आए हैं और इसीलिए स्व-वित्तपोषित कॉलेज और विश्वविद्यालय हर जगह धड़ाधड़ खुल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सरकार ने उच्च शिक्षा से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया हो, है ना?

और सबसे बुरी बात यह है कि समाज की सेवा के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित करने वाले ट्रस्ट अब स्व-वित्तपोषित संस्थान बन गए हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा के निजीकरण को खुली छूट दे दी है और यही परिणाम है। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद भी सरकार ने पर्याप्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने दी। इसलिए, राज्य सरकार ने जानबूझकर अनुदान प्राप्त कॉलेजों को बंद करने की योजना बनाई और नए अनुदान प्राप्त कॉलेजों की स्थापना की अनुमति नहीं दी। इस तरह निजीकरण लगभग

पूरा हो गया। शिक्षा अत्यधिक महंगी हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कारण राज्य सरकार की नीति है। गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर दावा करती है कि 2001 में गुजरात में 15 विश्वविद्यालय थे और आज 45 विश्वविद्यालय हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन विश्वविद्यालयों में फीस कितनी है और क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्वविद्यालयों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि अच्छे शिक्षक छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें।

वीजीआरसी दक्षिण गुजरात 2026 : यूक्रेनी और रूसी दूतावास के प्रतिनिधियों ने सूरत में ध्यान सत्र में भाग लिया

सूरत वीजीआरसी में पहुंचे आगंतुकों के लिए निःशुल्क ध्यान सत्र का आयोजन, अब तक 200 से अधिक अतिथि हुए शामिल

जीएनएस)। गांधीनगर : सूरत के हजीरा रोड स्थित ऑरो यूनिवर्सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के अंतर्गत आगंतुकों के लिए विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया है। अब तक लगभग 200 अतिथि इस ध्यान सत्र में शामिल हो चुके हैं। समिट के पहले दिन यूक्रेनी दूतावास तथा दूसरे दिन रूसी दूतावास के प्रतिनिधियों ने इस ध्यान सत्र का लाभ उठाकर प्रसन्नता व्यक्त की। समिट के अंतर्गत श्री अरबिंदो इंटीग्रल लाइफ सेंटर की ओर से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक अलग-अलग बैच में आगंतुकों के लिए निःशुल्क ध्यान सत्र का आयोजन किया गया है। इस कैम्पस में आगंतुकों को ध्यानशाला और साउंड गार्डन (सेंसोरियम) में ध्यान कराया जाता है। पहले दिन विशेष ध्यान सत्र के अंतर्गत भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक, उनकी पत्नी श्रीमती काटेर्यना

बिला तथा कॉन्सुलेट जनरल सुश्री ऐना जैचेन्को ध्यान सत्र में शामिल हुए।

समिट के दूसरे दिन रूसी दूतावास की ओर से जीआर और फाइनेंस सेक्टर के प्रमुख श्री ज्लाटा एंटुशेवा और इंटररीजनल रिलेशंस के प्रमुख श्री अल्बर्ट सेफियुलिन ने ध्यान सत्र का लाभ उठाया।

इसके अलावा, जापान के प्रतिनिधि भी इस ध्यान सत्र में शामिल हुए।

इस विशेष ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। विदेश से आए प्रतिनिधि, डेलीगेट्स सहित राज्य पुलिस विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने भी इस ध्यान सत्र का लाभ लिया है।

वीजीआरसी के दौरान आगामी 5 मई तक हर किसी के लिए अलग-अलग बैच में ध्यान करने की व्यवस्था की गई है।

महुवा रेलवे स्टेशन पर ईमानदारी का सराहनीय उदाहरण-यात्री की खोई हुई राशि सुरक्षित लौटाई गई

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल अंतर्गत महुवा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला है, जिसमें एक यात्री की खोई हुई नकद राशि सुरक्षित रूप से उसके परिजनों को वापस लौटा दी गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2026 को बांद्रा–महुवा एक्सप्रेस के ए-1 कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री को रुमाल में बंधी हुई नकद राशि प्राप्त हुई। संबंधित यात्री ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उक्त राशि महुवा स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में जमा कराई तथा सूचित किया कि यह राशि संभवतः सीट संख्या 29 पर यात्रा कर रहे यात्री की हो सकती है, जो सावरकुंडला स्टेशन पर उतर गए होंगे।

स्टेशन प्रशासन द्वारा लगभग दो घंटे तक संबंधित यात्री की प्रतीक्षा की गई, किंतु कोई भी व्यक्ति दावा करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात स्टेशन अधीक्षक द्वारा बुकिंग एवं चेकिंग स्टाफ के सहयोग से संबंधित ट्रेन में सीट संख्या 29 पर यात्रा करने वाले यात्री का पीएनआर एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क स्थापित किया गया। संपर्क करने पर यात्री श्री परेश मेघानी, जिन्होंने बोरीवली से लिलिया मोटा तक यात्रा की थी, ने पुष्टि की कि उनका लगभग 3500 की राशि रुमाल में बंधी हुई ट्रेन में ही छूट गई थी। उन्होंने अपनी आयु लगभग 80 वर्ष बताते हुए स्वास्थ्य कारणों से स्वयं उपस्थित होने में असमर्थता जताई तथा अनुरोध किया कि उक्त राशि उनके परिजन को सौंप दी जाए।

दिनांक 02 मई 2026 को यात्री के परिजन श्री अश्विनभाई पड़रिया महुवा स्टेशन पहुंचे। आवश्यक पहचान प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात 3518 की राशि उन्हें सुपुर्द कर दी गई। यात्री एवं उनके परिजनों ने महुवा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों एवं भारतीय रेलवे के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों की ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता पर गर्व करता है तथा यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत प्रतिबद्ध है।